जल्दी आयेगी मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी व फार्मा पॉलिसी-मुख्यमंत्री

राइज़िंग राजस्थान हैल्थ प्री-समिट में 16,176 करोड़ के एम.ओ.यू. साइन हुए

जयपुर, 14 नवंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में आज राइज़िंग राजस्थान स्वास्थ्य प्री-समिट में स्वास्थ्य, चिकित्सा और आयुष क्षेत्र के निवेशकों के साथ 16,176 करोड़ रुपये के एम.ओ.यू पर हस्ताक्षर किये गए। आज किए गए एम.ओ.यू. के साथ ही

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रसन्नता व्यक्त की कि इस प्री-समिट में 2,157 करोड़ रुपये के एम.ओ.यू. आयुष क्षेत्र में हुए।**

"राइज़िंग राजस्थान" ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के बैनर तले स्वास्थ्य क्षेत्र में हस्ताक्षरित कुल निवेश प्रस्तावों का आंकड़ा 25,400 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

आज किए गये एम.ओ.यू. में स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र के लिए 14,000 करोड़ रुपये के निवेश के लिए एम.ओ.यू. हुए, जबकि आयुष क्षेत्र में 2,157 करोड़ रुपये के निवेश एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए गए।

इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित करके हमारी सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि हम न केवल न केवल एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं बल्कि अगले 3-4 वर्षों में उन्हें धरातल पर भी उतारने जा रहे हैं।

राइज़िंग राजस्थान स्वास्थ्य प्री-समिट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में 16,176 करोड़ रुपये के एम.ओ.यू पर हस्ताक्षर हुए।

आयुष क्षेत्र में हुए 2,157 करोड़ रुपये के एम.ओ.यू. पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि हमने आयुष क्षेत्र में बड़ी संख्या में एम.ओ.यू. किए हैं। आयुष न केवल भारत की विरासत और पहचान है, बल्कि यह दुनिया के सामने भारतीय संस्कृति और सदियों पुराने ज्ञान को भी प्रदर्शित करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा, स्वास्थ्य सेवा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता स्पष्ट है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र के लिए अब तक का सबसे अधिक 28,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। सरकार, राज्य की चिकित्सा पर्यटन क्षमता को अनलॉक करने के लिए नई फार्मा पॉलिसी और मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी भी लॉन्च करने जा रही है।

आज किए गए एम.ओ.यू. के जरिए निवेशकों ने जयपुर, अजमेर, जोधपुर, राजसमंद, सीकर, सिरोही सहित राज्य के प्रमुख क्षेत्रों में फार्मा इकाइयां, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, नर्सिंग कॉलेज, होम्योपैथी और आयुर्वेद कॉलेज, आयुष अनुसंधान पंचकर्म केंद्र, उन्नत आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है।

इस अवसर पर मौजूद राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा, ये नये निवेश न केवल राज्य में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए नए स्वास्थ्य सेवा संस्थान, मेडिकल कॉलेज और वेलनेस सेंटर लाएंगे, बल्कि युवाओं के लिए लाखों रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे।

कार्यक्रम के अंत में राजस्थान सरकार के चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीश कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

कर्नाटक में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुहिम शुरु की। इसीलि वे बार-बार केस कर रहे हैं।

मई 2023 में कांग्रेस 135 सीटों का शानदार बहुमत अर्जित कर कर्नाटक की सत्ता में आई है तब से ही मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार के बीच नेतृत्व के मुद्दे पर जंग छिड़े होने की अफवाएं चल रही है। अभी तक सरकार आराम से चल रही है। सार्वजनिक रुप से दोनों नेता एकजुट दिख रहे हैं और शिव कुमार ने मुख्यमंत्री के भाजपा के लिए किए गए दावे का भी समर्थन किया है।

उन्होंने बैगलौर में कहा कि रिश्वत की कथित पेशकश भाजपा के "ऑपरेशन लोटस" का हिस्सा थी।

इस पर कड़ा विरोध जताते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.बाय. विजयेन्द्र ने मुख्यमंत्री को चुनौती दी कि अपने आरोपों को साबित करें। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है और वे झूठे आरोप लगा रहे है, आपकी सरकार है, आपकी जांच एजेंसियां हैं आपकी नैतिक जिम्मेदारी है जनता को यह बताना कि रिश्वत की पेशकश किसन की थी वरना आपका बयान एक बचकाने राजनैतिक बयान से ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा सिद्धारमैया ने यह आरोप अपनी पार्टी व विधायकों पर नियंत्रण रखने और भ्रष्टाचार के मामलों से ध्यान हटाने के लिए लगाए हैं।

प्रदूषण के कारण दिल्ली के प्राइमरी स्कूल बंद

सभी प्राथमिक विद्यालयों को अगले निर्देश तक ऑनलाइन कक्षायें चलाने के आदेश

- **सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में प्रदूषण पर लगी याचिका पर 18 नवंबर को सुनवाई करेगा।**

नई दिल्ली, 14 नवंबर। दिल्ली में बढ़ ते प्रदूषण के कारण सभी प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अब पहली से पांचवीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन होंगी। मुख्यमंत्री आतिशी ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा "बढ़ ते प्रदूषण के स्तर के कारण, दिल्ली के सभी प्राथमिक विद्यालय ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करेंगे और अगले निर्देश तक जारी रखेंगे।" दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर सभी स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए और बच्चों के माता-पिता को इसकी जानकारी देने के लिए कहा है।

इसी के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उपायों को लागू करने का अनुरोध करने वाली याचिका को 18 नवंबर के लिए तुरंत लिस्ट करने पर गुरुवार को सहमति व्यक्त की। ज्ञातव्य है कि, याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया था कि दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर न बन जाये इसलिए याचिका को तत्काल सूचीबद्ध किया जाए। इसके बाद अदालत ने दिल्ली में प्रदूषण से जुड़ी याचिका पर 18 नवंबर को सुनवाई करने पर सहमति जता दी।

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं को बंद करने के आदेश में कहा गया है, "दिल्ली में शिक्षा निदेशालय (डीओई), एमसीडी, एनडीएमसी और डीसीबी के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रमुखों को कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए स्कूलों में कक्षाएं बंद करने का निर्देश दिया जाता है। स्कूलों के प्रमुखों को अगले आदेश तक इन कक्षाओं के छात्रों के लिए ऑनलाइन मोड में कक्षाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।"

दिल्ली सरकार के आदेश में यह भी बताया गया है कि एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप-3 लागू करने का आदेश दिया है। दिल्ली और एनसीआर में ए.क्यू.आई. 401-450 के बीच है।शहर में खराब वायु गुणवत्ता के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 15 नवंबर, 2024 की सुबह 8 बजे से जीआरएपी-गंभीर वायु गुणवत्ता के चरण के तहत सभी उपाय लागू किए जाएंगे। अब साल 2017 से पहले खरीदे गए वाहन, जो बीएस-3 या उससे कम मानदंड के हैं, उनके उपयोग पर बैन लगा दिया गया है।

ट्रम्प की, सरकारी खर्च कम करने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

1970 के दशक में केरल से संयुक्त राज्य अमेरिका गए थे। लेकिन दोनों "जन्मजात श्वेत अमेरिकी" नहीं हैं। मस्क दक्षिण अफ्रीका से हैं और रामास्वामी भारतीय मूल के हैं।

यदि ये दोनों व्यक्ति एक अच्छे ज्ञानी और शिक्षित पृष्ठभूमि से आते हैं, तो डॉनल्ड ट्रम्प किताबों और अध्ययन की दुनिया में लगभग अजनबी प्रतीत होते हैं। उनका जीवन संपत्ति और खर्च, जोखिमपूर्ण आदतों और चालबाजियों से भरा हुआ रहा है। उन्हें अमेरिकी अदालत द्वारा दोषी भी ठहराया गया है।

सरकारी सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए उनके चयन से उदार अमेरिकी नागरिकों और आम जनता को सिहरन हो सकती है। मस्क का यह दावा है कि उनके प्रस्तावों से अमेरिका के 6.5 ट्रिलियन डॉलर के बजट में से 2 ट्रिलियन डॉलर की कटौती की जा सकती है। इससे सरकारी एजेंसियों और विभागों से लाखों लोग सीधे बाहर हो जाएंगे और अन्य कई लोग अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित होंगे।

सरकार का आकार घटाने से अमेरिकी सामाजिक क्षेत्र के बजट के साथ -साथ उसकी विशाल सैन्य बजट में भी कटौती हो सकती है, विशेषज्ञों का कहना है। सरकार के आकार को घटाने के प्रयासों का विभिन्न प्रकार से असर हो सकता है, जिसका उन लोगों द्वारा कड़ा विरोध किया जा सकता है जो सरकारी अभिजात्य वर्ग में हैं या स्थापित राजनीतिज्ञ हैं। सबसे बड़ा विरोध राजनीतिक वर्ग से ही हो सकता है। राजनेता संघीय बजट पास करते हैं और प्रशासनिक राज्य का वह हिस्सा जो वित्तीय शक्तियों को नियंत्रित करता है, वह कांग्रेस है। राजनीतिक वर्ग इन अधिकारों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो सकता। विधानमंडल बजट पास करने पर जोर देगा और मस्क तथा रामास्वामी जैसे विशेषज्ञों के हस्तक्षेप को तवज्जो नहीं देगा।

बाल मुकुंदाचार्य...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

परिवाद में अधिवक्ता असलम ने बताया कि गत 21 अक्टूबर को शाम के समय बालमुकुंदाचार्य अपने कुछ लोगों के साथ बास बदनपुरा स्थित शिया समाज की वक्फ संपत्ति, इमाम बारगाह में जबरन घुस गए और अभद्रता करने लगे। इस दौरान वहां मौजूद बच्चे और पर्दानशीन महिलाएं भयभीत हो गईं।

वहां मौजूद इमाम ने विधायक को जूते खोलने को कहा तो विधायक बालमुकुंदाचार्य ने उन्हें आतंकी सहित अन्य अपशब्द बोले। इसके अलावा विधायक ने वक्फ बोर्ड की ओर से लगाए वक्फ संपत्ति के बोर्ड पर एतराज किया।

परिवाद में कहा गया कि विधायक ने अपने सहयोगी के माध्यम से घटना का सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण किया, ताकि समाज में धार्मिक वैमनस्यता बढ़े और परिवादी के धार्मिक स्थल की प्रतिष्ठा खराब हो। इस संबंध में शहर के ब्रह्मपुरी थाने में रिपोर्ट दी गई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने परिवादी को साक्ष्य पेश करने को कहा है।

क्या राजफैड ने ऑरिगो और श्री शुभम् ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को नहीं दी गई। बाद में 6 नवंबर को ई-मेल के जरिए यह प्लान भंडारण निगम से साझा किया गया, जिससे इस आशंका को और बल मिलता है कि यह "प्लान" पी.पी.पी. मोड पर कार्यरत दोनों कम्पनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है।

इस ई-मेल के जवाब में भंडारण निगम की ओर से 13 नवंबर को राजफैड प्रबंध निदेशक को पत्र लिखा गया। जिसमें भंडारण निगम के पास उपलब्ध केन्द्रवार "वैकेंट कैपिसिटी" (गोदामों की खाली क्षमता) की स्थिति से अवगत कराया गया। साथ ही कहा गया कि भंडारण प्रबंधक के साथ 2 दिन में राजफैड के अधिकारी गोदामों का संयुक्त निरीक्षण करके यह भी जांच लें कि, किन गोदामों में उपयुक्त सुविधाएं हैं अथवा नहीं।

साथ ही कहा गया कि, राजफैड ने अपने "मूवमेंट प्लान" में नहीं बताया है कि खरीद केन्द्रों से दलहन-तिलहन की कितनी टन उपज खरीदी जायेगी और उसे रखने के लिए भंडारण निगम के गोदामों में कितनी जगह चाहिए।

राजफैड के अधिकारियों के इस लापरवाही के कारण अगर किसी गोदाम की भराव क्षमता खत्म होने के बाद भी दहलन-तिलहन का स्टॉक बच जाता है तो उसे रखने के लिए भंडारण निगम को आनन-फानन में निजी गोदामों का सहारा लेना पड़ेगा, ऐसे में विभाग को बेवजह आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। जिसका सीधा असर इन कृषि उपज के बाजार भावों में भी तेजी के तौर पर दिखेगा।

पाठकों को बता दें कि, गोदामों में कृषि उपज रखते समय कई तरह की जांच होती है, जिनमें वजन मापना, नमी के स्तर की जांच, उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था, आपात स्थिति में कृषि उपज को सुरक्षित अन्यत्र शिफ्ट करने के इंतजाम, आगजनी अथवा अन्य हादसों से निपटने के उपाय, कीट सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। इन मापदण्डों की जांच के बाद ही गोदामों को कृषि उपज रखने के लिए सही माना जाता है।

गौवंश तस्कर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से संबंधित आरोप हैं। आरोपी खान का आपराधिक इतिहास उसे एक आदतन अपराधी बनाता है। ऐसे में जमानत पर छूटे रहने पर उससे ना केवल सार्वजनिक सुरक्षा का खतरा है, बल्कि गौवंश तस्करी में उसके अपराध का सिलसिला भी जारी रह सकता है। राज्य सरकार गोवंश तस्करी को रोकने के लिए उपाय कर रही है। सुप्रीम कोर्ट आरोपी की जमानत रद्द करता है तो इससे पशु क्रूरता व अवैध परिवहन मामलों के आरोपियों में कानून की सख्त कार्रवाई स्थापित होगी। इसलिए अदालत आरोपी को दी जमानत आदेश पर पुनर्विचार करे।

आप के महेश...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से वॉकआउट किया। कांग्रेस के पार्षदों ने मेयर-डिप्टी मेयर चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। कांग्रेस ने अगले दलित मेयर के लिए नियोजित सीमित कार्यकाल पर असंतोष व्यक्त करते हुए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव का बहिष्कार किया। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्षद सबीला बेगम ने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है और वह मेयर चुनाव में आप के उम्मीदवार का समर्थन करेंगी। उन्होंने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा कि कांग्रेस पार्टी का आदेश है कि 14 नवंबर को होने वाले मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में वोट नहीं करना है। इससे सीधा भाजपा को फायदा होगा। पिछले मेयर चुनाव में भी पार्टी के आदेश पर हमने वॉकआऊट किया था जिसकी वजह से हमारे वॉर्ड में हमें हमारी जनता का आक्रोश झेलना पड़ा और वार्ड में 50-50 लाख रुपए रिश्वत लेने के पोस्टर में जनता ने लगाए थे। मैं कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफ़ा देती हूं।

हाईकोर्ट ने 26 हजार प्राइमरी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गए हैं।

इस समय यह स्पष्ट नहीं है कि ममता बनर्जी सरकार इस संकट से कैसे निपटेगी। सरकार द्वारा नियुक्त शिक्षकों की नौकरी चली गई है, जो लोग इन नियुक्तियों को चुनौती दे रहे हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, और इनकी संख्या बहुत बड़ी है। अदालत के निर्णय ने दिखा दिया है कि तृणमूल नेता कितने भ्रष्ट रहे हैं।

विशेष रूप से, क्योंकि, तृणमूल कांग्रेस ने, इस निर्णय को टालने और रद्द करवाने के लिए हर तरह की कोशिश की थी। पार्टी ने भारी भरकम राशि खर्च करके हाई प्रोफाइल वकील अभिषेक मनु सिंघवी की सेवाएं ली थीं। सभी विपक्षी पार्टियों ने, शिक्षकों की नियुक्ति बर्खास्त करने के आदेश को चुनौती देने के सरकार के निर्णय की भारी आलोचना की थी। अब सरकार की स्थिति बहुत खराब है और विपक्षी पार्टियां हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गई हैं।

ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामूला...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्थित है।

बेहद महत्वपूर्ण 3,209 मीटर लम्बी टी-वन सुरंग भी पूरी बन गई हैं। इसके निर्माण में काफी भौगोलिक व तकनीकी चुनौतियां आईं थीं। अब यहां पटरियां बिछाने का काम चल रहा है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूर्व में घोषणा की थी कि यू.एस.बी.आर.एल. (उधमपुर, श्रीनगर, बारामूल) दिसम्बर 2023 या जनवरी 2024 तक पूरा हो जाएगा। अब चूंकि टी-वन की बाधा पार हो गई है तो अगले वर्ष के आरंभ तक ट्रैक चालू हो जाएगा। पर अब लोड डिफ्लैक्शन टैस्ट की नई बहस छिड़ गई है प्रोजैक्ट पर और देरी हो सकती है।

मुम्बई एयर पोर्ट को बम की धमकी मिली

मुंबई, 14 नवंबर। मुंबई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मुंबई डोमेस्टिक एयरपोर्ट (टी1) पर सीआईएसएफ कंट्रोल रूम को बुधवार दोपहर को धमकी की कॉल मिली, जिसमें दावा किया गया कि मोहम्मद नाम का एक शख्स विस्फोटक सामाग्री लेकर मुंबई से अजरबैजान जा रहा है। इस कॉल से एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। सी.आई.एस.एफ. की टीम ने तुरंत इस मामले को गंभीरता से लिया और सहार पुलिस स्टेशन को अलर्ट किया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों की एक टीम को एयरपोर्ट पर तैनात किया गया और विस्तृत जांच शुरू की गई। सूत्रों के अनुसार, कॉल करने वाले ने किसी खास फ्लाइट का जिक्र नहीं किया और दोपहर करीब 3:00 बजे के आसपास अचानक कॉल बंद कर दी। इसके बाद अधिकारियों ने इस कॉल की जांच शुरू कर दी और संदिग्ध के बारे में जानकारी जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

राष्ट्रदूत हिन्दु संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाईन्ट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513 **कोटा कार्यालय :** पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033 **बीकानेर कार्यालय :** कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 **अजमेर कार्यालय:** राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908